



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 1982/फाल्गुन 14, 1903

No. 85]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 1982/PHALGUNA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1982

का० आ० 125(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/82—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 134(अ)/18 कक/आई०डी०आर०ए०/79 तारीख 13 मार्च, 1979 द्वारा यथा उपांतरित आदेश सं० का० आ० 529(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/74 तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, बंद और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स इंडिया बेल्टिंग एंड काउन्सिल लिमिटेड, सारसपुर, पश्चिमी बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) तारीख 6 सितम्बर, 1975 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 512(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 4 सितम्बर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 5 सितम्बर, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 749(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/80, तारीख 5 सितम्बर, 1980 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 5 सितम्बर, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष का और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के अधीन उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 684(अ)/18 कक/आई०डी०आर०ए०/81, तारीख 4 सितम्बर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 5 मार्च, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छः महीने की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा छह मास की और अवधि के लिए जारी रखा जाए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेदन देती है कि उक्त आदेश, 5 सितम्बर, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, यह छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० 2/14/80-सी० यू० सी०]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 1982

S.O. 125(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas, by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)/18AA/IDRA/74 dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134 (E)/18AA/IDRA/79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, the Closed and Sick Industries

Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 512(E)/18AA/IDRA/79, dated the 4th September, 1979, the duration of the said order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 5th September, 1980 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 749(E)/18AA/IDRA/80, dated the 5th September, 1980, the duration of the said order was further extended for a further period of one year upto and inclusive of the 5th September, 1981 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 684(E)/18AA/IDRA/81, dated the 4th September, 1981, the duration of the said order was further extended for a further period of six months upto and inclusive of the 5th March, 1982 ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 5th September, 1982.

[F. No. 2(14)/80-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.